



प्रेषक,

उदय प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग-9 (बजट)

लखनऊ: दिनांक 06 मई, 2026

विषय: मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीड, लखनऊ में आने वाले वादकारियों की सुविधा हेतु मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ परिसर के गेट-8 के समीप स्थित डिस्पेन्सरी के पीछे के क्षेत्र का नवीनीकरण व संशोधन करते हुए कवर्ड शेड एवं वाल के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने के पत्र संख्या-2446/ इन्फ्रा एच.सी./2026 सेल दिनांक 31.03.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीड, लखनऊ में आने वाले वादकारियों की सुविधा हेतु मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ परिसर के गेट-8 के समीप स्थित डिस्पेन्सरी के पीछे के क्षेत्र का नवीनीकरण व संशोधन करते हुए कवर्ड शेड एवं वाल के निर्माण कार्य हेतु आवश्यक धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की अपेक्षा की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीड, लखनऊ में आने वाले वादकारियों की सुविधा हेतु मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ परिसर के गेट-8 के समीप स्थित डिस्पेन्सरी के पीछे के क्षेत्र का नवीनीकरण व संशोधन करते हुए कवर्ड शेड एवं वाल के निर्माण कार्य हेतु मूल्यांकित धनराशि रु0 68.36 लाख (जी0एस0टी0 सहित) (रुपये अड़सठ लाख छत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उपर्युक्त निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 कार्यदायी संस्था नामित है।
- (2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत किया जा रहा है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी मद/कार्य में किया जायेगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि किसी बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।
- (5) कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अवशेष धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा करायी जाये।
- (6) इस सम्बन्ध में सुसंगत शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि का उपभोग चालू वित्तीय वर्ष में अतिशीघ्र कर लिया जायेगा।
- (8) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2025/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-04-मा0 उच्च न्यायालय में निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य "के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2025/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 द्वारा प्राप्त प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उदय प्रताप सिंह)

प्रमुख सचिव।

संख्या-106/2026/1316941(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2026-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2-प्रधान महालेखाकार(लेखा परीक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 3-वरिष्ठ निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ।
- 4-निजी सचिव, अध्यक्ष, अवस्थापना, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को मा0 अध्यक्ष के अवगतार्थ।
- 5-जनपद न्यायाधीश, लखनऊ।
- 6-निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7-कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ के माध्यम से।
- 8-निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
- 9-परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 हाईकोर्ट ईकाई-1 लखनऊ।
- 11-वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12
- 12-गार्डबुक।

आज्ञा से,

(डा0 सत्यवान सिंह)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।